आर्थिक समीक्षा

2022-23

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली–110001
जनवरी, 2023

विषय सूची

	vii	*प्रस्तावना*
	xi	*आभारोक्ति*
	xiii	*संकेताक्षर*
	xxxi	*तालिकाओं की सूची*
	xxxiii	*चित्रों की सूची*
	xli	*बॉक्स की सूची*
अध्याय सं.	**पृष्ठ सं.**	**अध्याय का नाम**
1		**अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 : पूर्ण सुधार**
	3	वैश्विक अर्थव्यवस्था विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रही है
	9	भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रोइकॉनॉमिक और विकास संबंधी चुनौतियाँ
	12	भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास संचालक
	19	भारत का समावेशी विकास
	22	आउटलुक 2023-24
2		**भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य: आशापूर्ण दृष्टि और उम्मीद के साथ**
	24	परिचय
	25	उत्पाद और पूंजी बाजार में सुधार
	28	नए भारत के लिए सुधार - सबका साथ सबका विकास
	36	2014 के बाद आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों की वापसी
	39	इस दशक में ग्रोथ मैग्नेट (2023-2030)
3		**राजकोषीय विकास - राजस्व सुधार**
	42	परिचय
	42	केंद्र सरकार की आय में वृद्धि
	54	राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का अवलोकन
	61	सरकार का ऋण प्रोफाइल
	67	निष्कर्ष
4		**मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: एक अच्छा वर्ष**
	79	मौद्रिक विकास
	82	नकदी की स्थिति
	83	मौद्रिक नीति संचरण
	84	जी-सेक बाजार में विकास
	85	बैंकिंग क्षेत्र
	88	सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली और ऋणमुक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा सहायता प्राप्त ऋण वृद्धि
	89	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का सुधार जारी है
	91	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत की गई प्रगति
	94	पूंजी बाजार में विकास
	102	अन्य विकास
	106	आईएफएससी - जीआईएफटी सिटी

109 बीमा बाजार में विकास
113 पेंशन क्षेत्र
116 दृष्टिकोण

5 **कीमतें और मुद्रास्फीतिः नाज़ुक परिस्थितियों पर कामयाबी**
118 परिचय
120 घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति
129 घरेलू थोक मूल्य मुद्रास्फीति
133 ईंधन मूल्य मुद्रास्फीतिः वैश्विक कच्चे तेल की घटती कीमत
134 डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति का अभिसरण
137 मुद्रास्फीतिक संभावनाओं में गिरावट
138 मूल्य स्थिरता के लिए मौद्रिक नीतिगत उपाय
139 आवासन मूल्यः महामारी के बाद उभरता हुआ आवासन क्षेत्र
142 भेषज मूल्य निर्धारण को नियंत्रित रखना
142 निष्कर्ष

6 **सामाजिक अवसंरचना और रोजगारः व्यापक व्यवस्था**
146 परिचय
147 क्षेत्र के बढ़ते महत्व को गति देने के लिए सामाजिक क्षेत्र व्यय
149 मानव विकास मानदंडों में सुधार करना
151 आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का परिवर्तन
153 प्रगामी श्रम सुधार उपाय
155 आधारः विशिष्ट पहचान की कई उपलब्धियां
157 रोजगार प्रवृतियों में सुधार करना
174 सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना
182 मिशन मोड में कार्यबल को नियोजनयोग्य कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित करना
185 सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा
199 आपातकाल के लिए सामाजिक संरक्षक
200 भारत की आकांक्षी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास
212 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणः गेम चेंजर
213 समावेशी विकास के लिए ग्रामीण शासन में सुधार करना
215 निष्कर्ष और वे-फॉरवार्ड

7 **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणः भविष्य का सामना करने की तैयारी**
217 परिचय
221 भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई पर प्रगति
231 संधारणीय विकास के लिए वित्त
234 सीओपी-27 में लिए गये प्रमुख निर्णय
235 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल
236 अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित पहल
242 निष्कर्ष

8 **कृषि और खाद्य प्रबंधनः खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक**

243 परिचय
245 खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन
246 उत्पादन की लागत पर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
246 कृषि संबंधी ऋण तक पहुंच में वृद्धि
247 फार्म मशीनीकरण- उत्पादकता में सुधार की कुंजी
247 रसायन मुक्त भारतः जैविक और प्राकृतिक खेती
248 कृषि में अन्य महत्वपूर्ण पहलें
252 संबद्ध क्षेत्र - पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन हाल के वर्षों में तेजी पकड़ रहा है।
253 सहकार-से-समृद्धिः सहयोग से समृद्धि तक
255 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र-सूर्योदय क्षेत्र
258 निष्कर्ष

9 **उद्योगः स्थायी विकास**

261 परिचय
262 औद्योगिक विकास के लिए मांग प्रोत्साहन
265 उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया
269 उद्योग के लिए बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि
270 विनिर्माण क्षेत्र में लचीला एफडीआई अंतर्वाह
272 औद्योगिक समूह एवं उनकी चुनौतियां
284 वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की संभावनाएं
291 निष्कर्ष और दृष्टिकोण

10 **सेवाएंः शक्ति का स्रोत**

293 परिचय
294 उच्च-आवृत्ति संकेतकों का रुझान
297 प्रमुख सेवाएंः उप-क्षेत्रवार प्रदर्शन
310 आउटलुक

11 **वैदेशिक क्षेत्रः सतर्क और आशावान**

312 परिचय
313 वैश्वीकृत संसार के लाभ उठाने में मददगार व्यापार
326 चुनौतीपूर्ण अवधि में भुगतान संतुलन
333 वैश्विक विकास के साथ घटती बढ़ती विनिमय दर
335 अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थितिः भारत की ठोस वित्तिय स्थिति का प्रतिबिम्ब
336 सुरक्षित एवमं ठोस वैदेशिक ऋण स्थिति
339 सतर्क और आशावान वैदेशिक क्षेत्र की स्थिति

12 **भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचनाः संभावित विकास को प्रोत्साहन**

343 परिचय
345 भारत में अवसंरचना के विकास के लिए सरकार की परिकल्पना और दृष्टिकोण
352 भौतिक अवसंरचना क्षेत्रों में विकास
360 डिजिटल अवसंरचना में विकास
371 निष्कर्ष/आउटलुक

प्रस्तावना

वर्ष 2023 की आर्थिक समीक्षा अवधि वैश्विक स्तर पर अनिश्चतापूर्ण है। अभी महामारी से उबर ही रहे थे कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ गया। भोजन, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति की दर में तेजी आई, उन्नत देशों के केन्द्रीय बैंकों ने प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी मौद्रिक नीति को सख्त किया। कई विकासशील देशों, विशेषरूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को कमजोर मुद्रा, उच्च आयात की कीमतों, जीवन यापन की बढ़ती लागत और मजबूत डॉलर के मेल के कारण गंभीर आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, जिससे सेवा और अधिक महंगी हो गई और इससे उबरना काफी मुश्किल साबित हुआ।

वर्ष 2022 की द्वितीय छमाही में सरकारों और परिवारों को राहत मिली। वस्तुओं की कीमतें अधिक बढ़ी और फिर कम हुईं। कुछ समय बाद विकट परेशानी से राहत मिली। हालांकि, कुछ वस्तुओं (जैसे कच्चा तेल) की कीमतें अपने महामारी-पूर्व स्तर से काफी ऊपर बनी हुई हैं। डॉलर की कीमत में भुगतान करने वाले आयात पर निर्भर देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक मंदी के फलस्वरूप वैश्विक मंदी में तिहरी राहत मिली है। जब वस्तुओं की कीमतों में कमी होती हैं, अमेरिकी ब्याज दरें अधिक हो जाती हैं, जैसा कि अमेरिकी डॉलर के साथ होता है। पूंजी और चालू खाता असंतुलन कम हो जाता है।

वर्ष 2023 के शुरूआत में ही चीन ने अपनी जीरो कोविड नीति के उलट, अपने रवैया उजागर कर दिया। अप्रत्याशित हल्की सर्दी के फलस्वरूप परिवार संबंधी ईंधन की कीमतों में होने वाली वृद्धि से अप्रभावित रहे, जो उनकी विक्रय आय को अत्यधिक प्रभावित कर सकती थी, इससे यह आशा जगी है कि मंदी के दौर से यूरो जोन व्यवस्था बाल-बाल बच जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की शीर्ष मुद्रास्फीति दर में गिरावट आने से, नीतिगत दरों का धीरे-धीरे बढ़ना निश्चित है। इसी प्रत्याशा में, बांड प्रतिफलों में कमी आई है, और अप्रत्याशित वित्तीय प्रणाली के दबाव से संयुक्त राज्य अमेरिका के अप्रभावित रहने की संभावना कम है।

निर्यात पर निर्भर, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने की संभावना कम है और उनकी आर्थिक गतिविधियों की बहाली से उन्हें उम्मीदें बंधी हैं, परन्तु यह उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर हैं। पूर्वानुमानित मांग से पहले उच्च मांग के कारण औद्योगिक धातुओं की कीमतों की तरह ही कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। अटलांटिक के दोनों ओर श्रम मजदूरी समझौतों में आरोही संशोधन हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरो जोन की सार्थक ब्याज दर में कटौती शायद आशा अनुरूप त्वरित गति से नहीं हैं। इस वर्ष के पूर्वानुमान वस्तु स्थिति से बहुत दूर हैं और देशों और परिवारों के लिए यह आश्चर्य का विषय हो सकता है।

वर्ष 2022, भारत के लिए खास रहा है। यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करता है। मौजूदा डॉलर के मापदण्ड के अनुसार भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। वास्तव में, मार्च 2023 को समाप्त हो रहे वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह विगत वित्त वर्ष की 8.7 प्रतिशत की वृद्धि की राह पर है। उपभोक्ता वस्तुओं में धीमी गती से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6.0 प्रतिशत से नीचे है। थोक कीमतें 5.0 प्रतिशत से कम की दर से बढ़ रही हैं। वित्त वर्ष के प्रारंभिक नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2021-22 की समान अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तेल की उच्च कीमत ने भारत के आयात बिल को बढ़ा दिया है और व्यापारिक घाटे के कारण हुए चालू खाते के घाटे को लेकर चिंताएं बढ़ीं हैं और वर्ष के बीतने के साथ-साथ वित्त पोषण कम होता गया। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर सुविधापूर्ण है और बाह्य ऋण कम हैं।

भारत में मानसून अच्छा रहा और जल संग्रह का स्तर पिछले वर्ष तथा विगत दस वर्षों के औसत से अधिक रहा है। आधुनिक, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सदी की आगामी पच्चीस वर्ष की यात्रा के अपने '*अमृत काल*' में प्रवेश करने के समय भारत की अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत स्थिति में है। सावधानीपूर्वक तथा सर्तकता से अपनाई गई नीतियों ने यह सुनिश्चित हुआ है कि रिकवरी ठोस एवं सतत् है। यही वह संदर्भ है, जिसका आर्थिक समीक्षा, हाल ही के विगतकाल के आलोक में, वर्तमान अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करता है और आगामी वर्षों में इसकी संभावनाओं का परीक्षण करता है। इससे पहले मैं आपको वर्ष 2022-23 के आर्थिक समीक्षा का भीतरी सिंहावलोकन प्रस्तुत करूं, यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष अभी जारी है, और समीक्षा केवल नौ महीनों या अधिकतम आठ महीनों के आंकड़ों पर आधारित है।

परिपाटी के अनुसार, प्रथम अध्याय में अर्थव्यवस्था की स्थिति के परीक्षण के बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि यह अर्थशास्त्र और राजनीति की दुनिया के उतार-चढ़ाव के एक और वर्ष के रूप में अर्थव्यवस्था कैसे उभरी। महामारी के प्रभाव के कम होने के साथ ही जापान में मौसमी फ्लू ढलान पर है, और शायद डेनमार्क में पहले ही समाप्त हो चुका है। अध्याय 2 भारत की मध्यावधि के आर्थिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है और इसकी बेहतरी के आकलन के साथ समाप्त होता है। यह वित्तीय चक्रों तथा मध्यम अवधि के आर्थिक विकास को प्रभावित करने में इसकी भूमिका का विश्लेषण करता है। पिछले दशक में भारत के वित्तीय चक्र में गिरावट आई है, क्योंकि सहस्त्राब्दि के प्रथम दशक में ऋण विस्तार अंततः अस्थिर साबित हुआ। विश्व के वित्तीय इतिहास से पता चलता है कि ये परिणाम चौंकाने वाले थे। प्रचुर मात्रा में आए पूंजी प्रवाह से प्रेरित, ऋण का तीव्र विस्तार, सदैव वित्तीय संकट की भविष्यवाणी का

संकेत देतें हैं। भारत भी कोई अपवाद नहीं रहा। इस अध्याय से पता चलता है कि वित्तीय दबाव की अवधि के दौरान सरकार ने कैसे अर्थव्यवस्था को संचालित किया, जिसमें कार्पोरेट, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग बैंलेंस-सीट को दुरूस्त किया और सुधारों की वापसी की। संकट में भी संभावना की तलाश करते हुए सरकार ने बुनियादी ढांचें में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया ताकि निजी क्षेत्र के निवेश, पारिश्रमिक और समृद्धि के लिए जमीन तैयार की जा सके। इसमें सरकार द्वारा वर्ष 2014 से शुरू किए गए शासन के प्रक्रियागत सुधारों और व्यापक संरचनात्मक सुधारों को दर्ज किया गया है।

जहां वर्ष 2014 से पहले के सुधारों ने उत्पाद तथा पूँजी बाजार को पुष्ट किया, वहीं 2014 के बाद किए गए सुधारों ने जीवन यापन को सुगम बनाने और आर्थिक दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यवसाय पर बल दिया। ये नीतियां जिन प्रमुख सिद्धांतों पर टिकी हुई हैं, वे सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर रहे हैं, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था को अपना रहे हैं, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर रहे हैं और कृषि उत्पादकता में सुधार कर रहे हैं। साफ-सुथरी, स्पष्ट और मजबूत बैलेंस-सीट और सुधारों से होने वाले भुगतान से भारत की अर्थव्यवस्था में संभावित वृद्धि हुई है और अर्थव्यवस्था की अपनी संभावित वृद्धि की क्षमता बढ़ी है। अनावश्यक दावे किए बिना, यह अध्याय भारत की मध्यम अवधि के दृष्टिकोण संबंधी आशावादी निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है।

अध्याय 3, भारत की राजकोषीय नीति प्रक्षेप पथ पर केन्द्रित है, और राज्यों तथा केन्द्र के लिए टिकाऊ एवं भरोसेमंद राजस्व के स्रोत के रूप में माल और सेवा कर की प्रगति का परीक्षण करता है। आगामी वर्षों में, भारत के जनसांख्यिकीय लाभ और वार्षिक नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के औसतन लगभग 10 से 12 प्रतिशत रहने की संभावना को देखते हुए राजकोषीय मापदंडों में सुधार जारी रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि वृद्धि ही भारत के राजकोषीय संतुलन को संचालित करती है और यही सच है। यह भी संभव है कि भविष्य में राजकोषीय विषय राजकोषीय प्रोत्साहन में बदल जाए, चूंकि सार्वजनिक व्यय में ब्याज के भुगतान के वर्तमान शेयर को कम करने से सरकार की उधार लागत में कमी आएगी तथा इससे आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

अध्याय 4 मुद्रा, बैंकिंग और पूंजी बाजार से संबंधित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर पड़ने वाली महंगाई की मार के द्वितीय चरण के प्रभावों से बचाने के लिए ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि की है। इसने डॉलर की मजबूती के एक वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की सापेक्ष स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाई। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता रही। भारत का आयात क्षेत्र और बाह्य ऋण अनुपात चिंता का विषय नहीं है, और काफी हद तक यह आरबीआई के कुशल प्रबंधन के कारण हुआ है। भारत का पूंजी बाजार ऐतिहासिक सफलता की कहानी कह रहा है। भारतीय शेयरों के अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क सूचकांकों ने अपने उभरते बाजार का बेहतर प्रदर्शन किया है, और अपने वैश्विक समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है। संक्षेप में, वर्षों से भारतीय शेयरों ने निवेशकों को अच्छा प्रतिफल दिया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को इससे काफी लाभ हुआ है। पिछले दो वर्षों में भारतीय शेयरों में बड़ी संख्या में भारतीय घरेलू खुदरा निवेशकों की भागीदारी में भी वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021 और 2022 में भारतीय शेयरों के प्रदर्शन को देखते हुए न केवल उनके निवेश ने समय-समय पर होने वाले पोर्टफोलियो के बहिर्वाह के प्रभाव को सहन ही किया है, बल्कि इन्होंने अपने धन-भंडारण में भी इजाफा किया।

अगले अध्याय में, वर्ष भर की कीमतों संबंधी भारत के थोक एवं खुदरा मूल्यों के अभिसरण का वृतांत प्रस्तुत किया गया है। मई 2022 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 16.6 प्रतिशत हो गई और थोक मूल्य मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के बीच का अंतर बढ़ गया। जब थोक मूल्य मुद्रास्फीति अधिक होती है, तो हमेशा एक जोखिम बना रहता है कि यह खुदरा कीमतों को प्रभावित करेगी। वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी आने और सरकार द्वारा उनकी घरेलू कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण वर्ष के अंत तक दोनों के बीच की खाई या रूकावट समाप्त हो गई।

विगत से आगे बढ़ते हुए, हम भारत के सामाजिक क्षेत्र (अध्याय-6) और उसके बाद जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण को (अध्याय-7) शामिल कर रहे हैं, जिसका महत्व भी कम नहीं है। समाज कल्याण सरकार के लिए 'उपसंहार' नहीं है बल्कि उसका मूलमंत्र है। इस अध्याय में सरकार द्वारा समाज कल्याण के लिए अपनाए गए व्यापक और 'कोई भी पीछे न छूटे' दृष्टिकोण को इस अध्याय में महत्व दिया गया है। इस अध्याय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विशेष रूप से महामारी के दौरान लक्षित लाभार्थियों तक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग ने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, 'आधार' के प्रयोग और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की विभिन्न पहलों के माध्यम से हो रहे नागरिकों के जीवन में परिवर्तन इस अध्याय के मुख्य आकर्षण हैं। इस अध्याय के तेरह बॉक्सों, जो एक बड़ी संख्या है - में समाज कल्याण योजनाओं तथा उनके वितरण में असंख्य नवाचारों की एक अभिस्वीकृति है, जिसे सरकार ने अपनाया और कार्यान्वित किया है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, वैश्विक स्तर पर न केवल ज्वलंत मुद्दे हैं बल्कि भारत के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) से सर्वाधिक सशक्त जलवायु कार्रवाइयों में से एक का नेतृत्व

कर रहा है, विश्व स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इसमें शामिल है। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, देश ने अपनी जलवायु महत्वाकांक्षा को कई गुना बढ़ाया है।

देश के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए कृषि क्षेत्र की स्थिती महत्वपूर्ण है। भारत ने घरेलू खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है और हाल के वर्षों में दुनिया के लिए कृषि उत्पादन का निवल निर्यातक बन गया है। कृषि क्षेत्र में क्षमता बढ़ी है। भारत में खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक के परिवर्तन काल और सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता को दिए जाने वाले महत्व को अध्याय 8 में दर्ज किया गया है।

अध्याय 9 से 12, में आर्थिक सर्वेक्षण के जीविकोपार्जन संबंधी विशेषताओं का वर्णन किया गया हैं। उसी क्रम में उद्योग, सेवा, बाह्य क्षेत्र और बुनियादी ढांचे का वर्णन है। भारतीय उद्योग, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक निवेश तथा नीतियों के बदौलत सुगम विकास पुनरुद्धार के शिखर पर है, जिसने व्यावसायिक परिस्थितियों को आसान बनाया है और व्यवहार्यता में सुधार किया है। उद्योग के लिए बैंक ऋण ने, विशेष रूप से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए गति पकड़ी है। अन्य बातों के अतिरिक्त, महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रति दक्षता से सुरक्षा और 'समय पर' से 'जरुरत पड़ने पर' के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में फिर से सुधार किया जा रहा है। सरकार को यहां बेहतर संभावना नजर आती है और उत्पादन-लिंक्ड-प्रोत्साहन योजना में इसका निवेश और प्रतिबद्धता भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। यह वैश्विक दृष्टि वाली औद्योगिक नीति है। अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण अंग बनने के लिए वास्तविक बोली लगाने के लिए अब भारत के पास भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा है। विगत आठ वर्षों में, इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार ने एक मंच तैयार किया है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह पूर्वानुमान उज्ज्वल है।

भारत का सेवा क्षेत्र शक्ति का एक स्रोत है और अधिक लाभ प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जीवंत विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को समायोजित करने और उनका पोषण करने के लिए भारत काफी सक्रिय है। इस क्षेत्र में निर्यात क्षमता के साथ-साथ निम्न से उच्च मूल्य वर्धित गतिविधियों तक, रोजगार और विदेशी मुद्रा तैयार करने और भारत की बाह्य स्थिरता में योगदान करने की पर्याप्त गुंजाइश है।

आयातित ईंधन पर निर्भरता के कारण बड़े व्यापारिक घाटे वाले देश के रूप में, विशेषकर बढ़ती तेल की कीमतों के दौरान, बाह्य क्षेत्र को हमेशा बारीकी से देखा जाता है। यह वित्त वर्ष ऐसा ही है। सरकार के विभिन्न अंगों ने यह सुनिश्चित किया कि अत्यधिक आपूर्ति अनिश्चितता और मूल्य अस्थिरता के एक वर्ष में, भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया। वैश्विक विकास को मंदी के कारण निर्यात वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन अप्रैल-दिसंबर 2022 में मौजूदा डॉलर में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का संयुक्त मूल्य अप्रैल-दिसंबर 2021 की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक रहा है। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमित रहा, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में भारत को शामिल करने में निवेशकों की रुचि अब भी काफी अधिक है। आने वाले वर्षों में '*गति शक्ति*' और 'राष्ट्रीय रसद नीति' से भारत की लागत और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है।

इससे हम सर्वेक्षण के बारहवें और अंतिम अध्याय में आते हैं। यह बुनियादी ढांचे की व्याख्या करता है। 'आखिरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है' एक पिष्टोक्ति है, लेकिन इस मामले में, यह एक सच्ची पिष्टोक्ति है। हमने हाल के वर्षों की भारत की सबसे अच्छी सफलता की कहानियों में से एक को अंतिम अध्याय के लिए रखा है। वर्ष 2019 में, भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के प्रति एक दूरदर्शी कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण अपनाया है। देश में बुनियादी ढांचे के विकास के व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए वित्त वर्ष 2020-25 के लिए लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उदय हुआ। जबकि, पिछले आठ वर्षों में सड़क, रेलवे और जलमार्गों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का काफी उन्नयन किया गया है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार कहानी का केवल एक भाग है; आधुनिकीकरण एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका दृढ़ता से प्रयास किया गया और प्रशंसनीय गति के साथ हासिल किया गया है।

अंत में, भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास न केवल संख्या और '*मील के पत्थर*' की कहानी है, बल्कि विचारशील विनियामक एवं नवोन्मेषी वास्तुकला की बानगी भी है, जिसने निजी क्षेत्र को नवाचार और निवेश करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ अपने सार्वजनिक सच्चरित्र को बनाए रखने में सक्षम बनाया है। अप्रयुक्त क्षमता अत्यधिक वृहद है, और देश को नवाचार जारी रखने की आवश्यकता है। डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे के साथ, इसे अपनी जगह बनाए रखने के लिए कार्यशील रहना होगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में विकसित हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था में हाल ही में गलतियां हुई हैं, यदि इतिहास मार्गदर्शक होता तो ऐसा होना अनिवार्य था। नतीजतन, वैश्विक सहमति के मंच के रूप में परिकल्पित, बोर्ड में बहुपक्षीय मंच अस्तित्व बचाने संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा हैं और आज उसे अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। भारत, अपने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक उद्भव के साथ, घटनाओं के क्रम को प्रभावित कर सकता है और इस प्रक्रिया में प्रासंगिकता की वैश्विक शक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को पूरा कर सकता है। यह विदित है कि भारत ने अपने अमृत काल के दौरान दिसंबर 2022 में जी-20 देशों की अध्यक्षता ग्रहण की है। वैश्विक समस्याओं के लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है, और वैश्विक समाधान के

लिए सहभागिता और सहयोग की आवश्यकता है। ''वसुधैव कुटुंबकम'' के प्रसंग के आधार पर: 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', भारत की वर्ष 2023 जी-20 की अध्यक्षता का उद्देश्य वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों का समन्वित समाधान करना है, जैसे कि 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, समय पर पर्याप्त जलवायु वित्त जुटाना, महामारी की तैयारी के लिए वित्तपोषण बढ़ाना, वैश्विक व्यापक आर्थिक कमजोरियों जैसे ऋण, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा और शहरी अवसंरचना का वित्तपोषण करना। भारत के लिए अध्यक्षता करना वैश्विक समुदाय के समक्ष भारतीय विकास की कहानी दिखाने का एक मंच है, विशेष रूप से जिस तरह से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने एक समावेशी जन-केंद्रित विकास प्रतिमान का समर्थन किया है। संक्षेप में, भारत के लिए जी-20 की अध्यक्षता करना अन्यथा रूप से खंडित वैश्विक व्यवस्था को एकजूट करने का एक अवसर है।

आर्थिक सर्वेक्षण को सार्वजनिक विचार के लिए रखना एक अधिगम जनित अनुभव है। यह निश्चयात्मक सोच, विचारों के निर्माण और उनकी प्रभावी अभिव्यक्ति का एक प्रयोग है। अर्थव्यवस्था के तर्ज पर ही, यह सदैव प्रगतिशील कार्य है। हालांकि सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है। इस दस्तावेज को एक साथ रखने वाले अधिकारियों का समूह कभी भी समान नहीं होता है और यह प्रत्येक वर्ष प्रकाशन को समृद्ध करता है। जबकि पुराने विचार अपने साथ अनुभव और विशेषज्ञता लाते हैं और नए प्रवेशकर्ता, जैसे कि 'आपका विश्वासी', नए दृष्टिकोण लाते हैं। मैं इस वर्ष के सर्वेक्षण में अपनी अंतर्दृष्टि, विषय विशेषज्ञता और अनुभव लाने के लिए उनमें से प्रत्येक का आभारी हूं। मैं विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, विनियामकों और विषय विशेषज्ञों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने समय पर सूचना सामग्री प्रदान की और इस प्रकाशन को सफल बनाया। मैं मसौदा तैयार करने में संपादकीय टीम को उनके सत्यनिष्ठ प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं।

देश की सभी आर्थिक गतिविधियों को एक छतरी के नीचे रखने और इसे अर्थशास्त्रियों की भांति संशोधित करने से लेकर सामान्य नज़रिये से परिष्कृत करने, संबंधी कार्य एक अहम प्रयास हैं। यह एक संतोषजनक और सार्थक अनुभव रहा है, क्योंकि इसने देश और इसके लोगों के प्रति मेरी आशा और विश्वास को मजबूत किया है। मुझे उम्मीद है कि सर्वेक्षण के आंकड़ों और विश्लेषण से अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को मदद मिलेगी।

विशेष रूप से, मुझे उम्मीद है कि यह पाठकों को इस महान राष्ट्र के भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। यह भरोसा दिलाता है, कि अगर यह बेहतर नहीं, तो कम से कम हर प्रकार से अपने अतीत की तरह गौरवशाली होगा।

(वी. अनंत नागेश्वरन)
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय, भारत सरकार

आभारोक्ति

आर्थिक समीक्षा 2022-23 सामूहिक कार्य और पारस्परिक सहयोग का परिणाम है। यह आर्थिक समीक्षा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा समय-समय की गई टिप्पणियों और उनकी अंतर्दृष्टि से अत्यंत लाभान्वित हुई है। यह समीक्षा माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, डॉ. भागवत किशनराव कराड और वित्त सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन, सचिव डीईए श्री अजय सेठ राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा, डीएफएस सचिव श्री विवेक जोशी और दीपम सचिव श्री तुहिन कांता पांडे द्वारा की गई टिप्पणियों और उनके सहयोग के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करती है।

इस समीक्षा में आर्थिक प्रभाग और प्रधान आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से जिन व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है, उनमें: राजीव मिश्रा, सैकत सरकार, चांदनी रैना, अनुराधा गुरु, साजू के. सुरेंद्रन, शशिकुमार एस., श्वेता कुमार, टी. गोपीनाथ, वसंती वी. बाबू, स्वेता सत्या, धर्मेंद्र कुमार, एम. राहुल, हरीश कुमार कल्लेगा, गुरविंदर कौर, दीपिका श्रीवास्तव, अमित श्योराण, श्रेया बजाज, मनोज कुमार मिश्रा, मेघा अरोड़ा, दीक्षा सुपयाल बिष्ट, रीतिका बंसल, मोहम्मद आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पायने, अभिनव बांका, शिवानी मोहन, सहर, मृत्युंजय कुमार, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, रोहित कुमार तिवारी, दीपद्युति सरकार, हेमा राणा, जेरिन थॉमस अब्राहम, सोनाली चौधरी, सुरभि सेठ, भारद्वाज आदिराजू, उन्नी नारायणन कुरुप, मीरा उन्नीकृष्णन, आकाश फजारी, सत्येंद्र किशोर, एस. रामकृष्णन, विशाल गोरी, रितेश कुमार, मीनाक्षी, मुना साह, मोहन सुना, गुलशन और अधिकारियों के निजी कर्मचारी शामिल हैं।

इस आर्थिक समीक्षा में जिन अधिकारियों की टिप्पणियों और इनपुट से विशेष लाभ मिला है उनमें जुबैर नकवी, विनोद कोतवाल, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, रवि दाधीच, प्रशांत कुमार राय, प्रोसेनजीत सान्याल, विशाल गोयल, अपराजिता त्रिपाठी, अपराजिता जैन, अबू हुजैफा, शिवा सिंह, पीयूष मिश्रा, अनुराग भटनागर, एस.वी. सिंह, वंदना गौतम, सिद्धार्थ शंकर, ज्योत्सना गुप्ता, विशाल, ए.आर. राव, डॉ. अंसी मैथ्यू, डॉ. दिगंबर स्वैन, डॉ. प्रतिभा ए, दिगंबर सिंह, नवीन कुमार, जतिंदर सिंह, रमेश यादव, गुलजार नटराजन, देवी प्रसाद मिश्रा, गौरव मसलदान, डॉ. सी. वनलालरामसांगा, रेणु लता, सुदीप्त भट्टाचार्य, ऋषिका चोरारिया, श्याम सुंदर पारुई, सौरभ गर्ग, आलोक शुक्ला, समीर कुमार, प्रवीण महतो, नीलांभुज शरण, अंशुमान कामिला, आर. राजेश, मनीष शर्मा, राकेश रंजन, डॉ. बिजय कुमार बेहरा, इंद्राणी कौशल, धीरेंद्र गजभिए, दीपिका रावत, अशोक कुमार, यशवंत सिंह, सुभाष चंदर, ए. श्रीजा, स्मृति शरण, वी. धन्या, इप्सिता पाधी, सत्यार्थ सिंह, रचित सोलंकी, अविलेश शर्मा, रितेश पटेल, अजय कुमार सिंह, दिव्या शर्मा, उमेश चंद्र, धर्मेंद्र, सीएम डे कर्मकार, धरम प्रकाश, सी. मोहनदास, ओ.पी. ठाकुर, दीपक मेहरा, शैलेंद्र मिश्रा, आलोक चंद्र, संतोष कुमार सिन्हा, संजीत सिंह, तनुश्री चंद्रा, सुरजीत कार्तिकेयन, दीक्षा सचदेवा, कुमार सुंदरम, डॉ. सुरेंद्र कुमार ए हिरवार, जमीरुद्दीन अंसारी, देबप्रसाद रथ, प्रभात कुमार, सुप्रियो मंडल, एलेक्स फिलिप, अक्षरा अवस्थी, प्रतिभा केडिया, जंग बहादुर सिंह, आशीष कुमार मल्लिक, वेंकटेश्वरन रामकृष्णन, प्रभात रथ, अनंत नारायण जी, सुजीत प्रसाद, राकेश गोयल, आशीष अग्रवाल, तेजस्वी गुप्ता, मेधा शेवर, सुधाकर शुक्ला, संतोष शुक्ला, सुशिर शर्मा, एडमिरल आर हरि कुमार, सौगत भट्टाचार्य, आशीष त्रिपाठी, देबाशीष पांडा शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों ने भी अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। हमें कई उद्योग निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे आरबीआई, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनपीपीए, आईएसए, सीईए, नैसकॉम, आईबीबीआई, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, ओ/ओ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एक्सिस बैंक, आईआरडीएआई से भी मदद मिली।

प्रशासनिक सहयोग मनीषा सिन्हा, मनोज सहाय, एंटनी सिरिएक, अपर्णा भाटिया, जसबीर सिंह, अरूप श्याम चौधरी, सुश्रुत सामंत, दलीप कुमार, सुनील कुमार गुप्ता, एस.के. अग्रवाल, दिनेश विश्वकर्मा, अवनीश अग्रवाल और डीईए के अन्य सदस्य द्वारा प्रदान किया गया। इस आर्थिक समीक्षा का हिंदी अनुवाद कार्य आनंद कुमार, पूरन सिंह तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के डॉ. सुरेश कुमार यादव, मनीष भटनागर, ओमप्रकाश सिंह, राजीव कुमार, अश्विनी कुमार, मनोज कुमार, रवि कुमार मीणा ने किया। समीक्षा के हिंदी संस्करण का टंकण कार्य भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड़, नई दिल्ली (मुद्रण निदेशालय) के शशिपाल सिंह रावत, अरुण कुमार, यतेन्द्र कुमार, संजय प्रसाद द्वारा किया गया। सर्वे का कवर पेज इज्जुर रहमान द्वारा डिजाइन किया गया। आर्थिक समीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों की पेज सेटिंग सिग्नेचर प्रिंटरर्स के इज्जुर रहमान, दीपक अग्रवार, गौतम हलदर, जफरुद्द और जगदीश ने की।

अंत में, इस आर्थिक समीक्षा से जुड़े समस्त कार्मिकों के परिजन भी हृदय की गहराइयों से आभार के पात्र हैं जिन्होंने इस कार्य के दौरान असीम धैर्य और उदारता का परिचय दिया।

वी. अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय
भारत सरकार

संकेताक्षर

एए	खाता समूहक
एएआई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
एएवाई	अंत्योदय अन्न योजना
एबी पीएम-जेएवाई	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
एबीडीएम	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
एबीपी	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
एबी-पीएमजेएवाई	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
एबीआरवाई	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीजीएम	अबू धाबी वैश्विक बाजार
एडीपी	आकांक्षी जिला कार्यक्रम
एडीएस	आकांक्षी जिले
एई	अग्रिम अनुमान
एईपीएस/एईपीएस	आधार युक्त भुगतान प्रणाली
एईएस	अग्रिम अर्थव्यवस्थायें
एएफसीएफटीए	अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र
एएफएसए	अल्बानियाई वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण
एजीईवाई	आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना
एएचएफ	किफायती आवास फंड
एएचआईडीएफ	पशफपालन अवसंरचना विकास निधि
एआई	आर्टिफीशियल इंटेलिजेंश
एआईडीसी	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर
एआईएफ	कृषि अवसंरचना कोष
एआईएम	अटल इनोवेशन मिशन
एआईएसएचई	उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
एकेएएम	आजादी का अमृत महोत्सव
एएमएफ	फ्रांस के ऑटोराइट डेस मार्च फाइनेंसर्स
एएनबी	आत्मनिर्भर भारत
एपीबी	आधार भुगतान फल
एपीईडीए	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एक्यूआर	आस्ति गुणवत्ता समीक्षा
एआरआर	औसत राजस्व दर
एएसईएएन	दक्षिण - पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ
एएसईईएम	आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण
एएसआई	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
एटीएमपी	विधानसभा, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग
एयूएम	प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों
बीसीडी	बुनियादी सीमा शुल्क
बीई	बजट अनुमान

बीईआई	व्यापार अपेक्षा सूचकांक
बीएफटी	बेयर फुट तकनीशियन
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय फनर्निर्माण बोर्ड
बीआईएस	अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बैंक
बीएमआई	बॉडी मास इंडेक्स
बीओई	बैंक ऑफ इंग्लैंड
बीओपी	भुगतान संतुलन
बीओटी	बिल्ड – ऑपरेट – ट्रांसफर
बीपीकेपी	भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति
बीपीओ	व्यापार प्रक्रिया बाहरी स्रोत से सेवाएँ प्राप्त करना
बीपीएस	आधार अंक
बीआरएपी	व्यापार सुधार कार्य योजना
बीआरएसआर	व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट
बीएससीसीएल	बांग्लादेश पनडुब्बी केबल कंपनी लिमिटेड
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
सीए	सहयोग समझौता
सीएबी	चालू खाता शेष
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सीएएमपीए	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
सीएएनआई	चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी
सीएपीईएक्स	पूंजीगत व्यय
सीबीएंडटी	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
सीबीडी	जैविक विविधता पर कन्वेंशन
सीबीडीसी	सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा
सीबीडीआर–आरसी	सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीएन	सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया
सीबीओई	शिकागो बोर्ड विकल्प एक्सचेंज
सीसीबी	पूंजी संरक्षण बफर
सीसीईएस	फसल काटने के प्रयोग
सीसीपी	केंद्रीय काउंटर पार्टियां
सीडी	कॉर्पोरेट कर्जदार
सीडीपी	क्लस्टर विकास कार्यक्रम
सीडीआरआई	आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
सीएफपीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीजीए	लेखा महानियंत्रक
सीजीसी	क्रेडिट गारंटी निगम

सीजीएसएस	स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
सीजीएसटी	केंद्रीय माल और सेवा कर
सीएचसी	कस्टम हायरिंग सेंटर
सीएचई	वर्तमान स्वास्थ्य व्यय
सीएचआईपीएस और साइंस एक्ट, 2022	अर्धचालक और विज्ञान अधिनियम, 2022 के उत्पादन के लिए सहायक प्रोत्साहन बनाना
सीआईबीआईएल	क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
सीआईसी	चलन में मुद्रा
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीआईआरपी	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीआईआरपी	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीआईटीईएस	वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन
सीएलएपी	व्यापक रसद कार्य योजना
सीएलएसएस	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
सीएम	महत्वपूर्ण खनिज
सीएमआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र
सीएमएसएस	केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी
सीओडी	वाणिज्यिक संचालन तिथि
सीओपी	पार्टियों का सम्मेलन
कोविड 19	कोरोनावाइरस रोग
कोविन	कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई-एएल	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर
सीपीआई-सी	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त
सीपीआई-आईडब्ल्यू	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक
सीपीआई-आरएल	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण मजदूर
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
सीआरएआर	कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो
सीआरएआर	सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी
सीआरपीएस	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
सीआरआर	नकद आरक्षित अनुपात
सीआरएस	सामुदायिक रेडियो स्टेशनों
सीआरजेड	तटीय विनियमन क्षेत्र
सीएससीएस	सार्वजनिक सेवा केंद्रों
सीएसडी	केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी
सीएसआई	वर्तमान स्थिति सूचकांक
सीएसआईएस	ब्याज सब्सिडी पर केंद्रीय योजना
सीएसआर	कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीटीडीपी	व्यापक दूरसंचार विकास योजना
सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
सीडब्ल्यूएस	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति

सीडब्ल्यूएसएन	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
सीवाईकेसी	सेंट्रल नो योर कस्टमर
डीएवाई-एनआरएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीएवाई-एनयूएलएम	दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
डीबीएफओटी	डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीबीयू	डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
डीसीआईएल	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
डीडीई	डिजिटल दस्तावेज निष्पादन
डीडीयूजीजेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीडीयू-जीकेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीएफसी	समर्पित मालभाड़ा गलियारा
डीएफआई	समर्पित वित्तीय संस्थान
डीएफआईएस	विकास वित्तीय संस्थान
डीएफएसए	दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण
डीजीसीआईएंडएस	वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीजीआरसी	जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति
डीआईआई	घरेलू संस्थागत निवेश
डीआईएसईआर	उद्योग, विज्ञान, ऊर्जा और संसाधन विभाग
डीएलसी	डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
डीएलआई	डिजाइन से जुड़ा प्रोत्साहन
डीएलटी	वितरित खाता प्रौद्योगिकी
डीएनबी	राष्ट्रीय बोर्ड के राजनयिक
डीओसीए	उपभोक्ता मामलों का विभाग
डीओपी	डाक विभाग
डीपीसीओ	औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश
डीपीआई	डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
डीपीआईआईटी	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीपीआर/डीपीआरएस	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरएएएस	ड्रोन-एज-ए-सर्विस
डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
डीआरटी	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डीएससीएस	जिला कौशल समितियां
ई पीपीओ	इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश
ई-बीजी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी
ई-बीएल	लदान का इलेक्ट्रॉनिक बिल
ईबीआर	अतिरिक्त-बजटीय संसाधन
ईसीबी	यूरोपीय केंद्रीय बैंक
ईसीबीएस	बाहरी वाणिज्यिक उधार
ईसीआईबी	बैंकों को निर्यात ऋण बीमा
ईसीएल	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
ईसीएलजीएस	आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना

ईसीआरपी	आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज
ईसीटीए	आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
ईसीटीएस	इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज
ईडीएलआई	कर्मचारी डीपोजिट लिंक्ड बीमा
ई-डीओ	इलेक्ट्रॉनिक वितरण आदेश
ईईडी	एंड-टू-एंड डिजिटाइज्ड
ईईई	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
ई-एफएमएस	इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम
ईकेवाईसी	इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक को जानें
ईएमडीईएस	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमईएस	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ई-एनएएम	राष्ट्रीय कृषि बाजार
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य - निधि संस्था
ईपीआई	निर्यात तैयारी सूचकांक
ई-पीओएस	बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु
ईपीआर	विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी
ई-पीआरएएन	इलेक्ट्रॉनिक-पेंशन सेवानिवृत्ति खाता संख्या
ईपीटीए	प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता
ईआरएंडडी	इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास
ईआरएस	निर्वाचित प्रतिनिधि
ईएसजी	पर्यावरण, सामाजिक और शासन
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईएसओपीएस	कर्मचारी स्टॉक विकल्प
ईटीएफ	विनिमय व्यापार फंड
ईयू	यूरोपीय संघ
ईवी	बिजली के वाहन
ईवीआईएन	इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क
ईवीएस	बिजली के वाहन
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
ईएक्सआईएम	निर्यात आयात
एफएजी	फेसलेस असेसमेंट ग्रुप
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफबीएस	विदेशी बैंक
एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफडीआईसी	फेडरल डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन
एफईडीएआई	फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एफईआई	भविष्य की उम्मीदों का सूचकांक
एफईआर	विदेशी मुद्रा भंडार
एफएफसी	पंद्रहवां वित्त आयोग
एफएफएस	स्टार्ट-अप के लिए फंडों की निधि
एफआईसी	पूर्ण टीकाकरण कवरेज
एफआईडीएफ	अवसंरचना विकास निधि

एफआईएफपी	विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल
फिन टेक	वित्तीय प्रौद्योगिकी
एफआईपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
एफआईपीएस	वित्तीय सूचना प्रदाता
एफआईयूएस	वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता
एफएलएफपीआर	महिला श्रम बल भागीदारी दर
एफएमआई	वित्तीय बाजार अवसंरचना
एफएमएसए	वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण
एफओएफ	फंडों की निधि
एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ	पब्लिक ऑफर पर फॉलो करें
एफपीओ	विदेशी डाकघर
एफपीओएस	किसान उत्पादक संगठन
एफपीएस	उचित मूल्य की दुकान
एफआरबीएम	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
एफआरएल	राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसआई	भारतीय वन सर्वेक्षण
एफएसआरए	वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण
एफटीए	विदेशी पर्यटकों का आगमन
एफटीएएस	मुक्त व्यापार समझौतों
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीटीएच	घर के लिए तंत्रिका
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीसी	आमान परिवर्तन
जीसीसी	वैश्विक योग्यता केंद्र
जीसीसी	खाड़ी सहयोग परिषद
जीसीईएस	सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण
जीसीएफ	हरित जलवायु कोष
जीसीटी	गतिशक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल
जीडीपी	सकल घरेलु उत्पाद
जीईएम	सरकारी ई-मार्केटप्लेस
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीएफसीएफ	कुल निश्चित पूंजी निर्माण
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीएचई	सरकारी स्वास्थ्य व्यय
जीएचजी	ग्रीनहाउस गैस
जीआईएफटी	गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
जीआईआई	ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
जीआईएम	हरित भारत मिशन
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीएमवी	सकल पण्य वस्तु मूल्य
जीएनआई	सकल राष्ट्रीय आय
जीएनपीएएस	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां

जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी–एसईसी	सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएन	माल और सेवा कर नेटवर्क
जीटीआर	सकल कर राजस्व
जीवीए	सकल मूल्य जोड़ा गया
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
जीडब्ल्यूएच	गीगा वाट घंटे
एचएएम	हाइब्रिड एनुइटी मॉडल
एचडीआई	मानव विकास सूची
एचईआई	उच्च शिक्षा संस्थान
एचएफसी	आवास वित्त क्षेत्र
एचएफसी	आवास वित्त कंपनियां
एचएफआई	उच्च आवृत्ति संकेतक
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एचपीआई	आवास मूल्य सूचकांक
एचपीओ	जलविद्युत खरीद दायित्व
एचएससीसी	अस्पताल सेवा परामर्श निगम
एचयूएफ	हिंदू अविभाजित परिवार
एचडब्ल्यूसीएस	स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
आईएआईएस	बीमा पर्यवेक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे
आईसीएफआरई	भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद
आईसीएमए	अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईसीटी	अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल
आईडी	पहचान दस्तावेज
आईएफपीआरआई	अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
आईएफएससी	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आईएफएससीए	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईजीसीआरएस	शुल्क की रियायती दर पर या निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात
आईजीएनडीपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
आईजीएनओएपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
आईजीएनडब्ल्यूपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
आईजीएसटी	एकीकृत माल और सेवा कर
आईआईएफटी	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

आईआईजी	इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईएमए	भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद
आईआईपी	अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
आईआईपीडीएफ	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना
आईआईएसईआर	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलएंडएफएस	इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज
आईएलडीएस	ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण
आईएलएमडीएस	नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण
आईएमबी	अंतर-मंत्रालयी बोर्ड
आईएमएफ	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमपीएस	तत्काल भुगतान सेवा
आईएमआर	शिशु मृत्यु दर
आईएनवीआईटी	इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
आईओएससीओ	प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन
आईओटी	थींग्स की इंटरनेट
आईपी	इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी
आईपीसीसी	जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर - सरकारी पैनल
आईपीओ	प्रथम जन प्रस्ताव
आईपीआर	इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी अधिकार
आईआर	भारतीय रेल
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण
आईएसए	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
आईएसएफआर	भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट
आईएसएस	ब्याज अनुदान योजना
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटी-बीपीएम	सूचना प्रौद्योगिकी-व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन
आईटीसी	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आईटीआईएस	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीआर	आयकर रिटर्न
आईडब्ल्यूएआई	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
आईवाईएम	बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष
जेएंडके	जम्मू और कश्मीर
जेएएम	जनधन-आधार-मोबाइल
जेसी	जॉब कार्ड
जेजेएम	जल जीवन मिशन
जेपीसी	संयुक्त संयंत्र समिति
जेआरएस	नौकरी प्रतिधारण योजना
जेएसएस	जन शिक्षण संस्थान
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केएलआई	कोच्चि से लक्षद्वीप द्वीप समूह तक सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी
केएमएस	खरीफ विपणन सीजन

केपीआई	मुख्य निष्पादन संकेतक
केआरसीएल	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलएएफ	लिक्वीडीटी एडजस्टमेंट सिलिटी
एलसी	लेटर ऑफ क्रेडिट
एलसीओएच	हाइड्रोजन की स्तरित लागत
एलडीसीएस	कम से कम विकसित देश
एलईएडीआईटी	उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह
एलईएडीएस	विभिन्न राज्यों में रसद आसान
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एलजीएससीएटीएसएस	कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना
एलएचएंडडीसी	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
एलएलपी	सीमित दायित्व भागीदारी
एलएमटी	लाख मीट्रिक टन
एलपीजी	तरल पेट्रोलियम गैस
एलपीआई	रसद प्रदर्शन सूचकांक
एलएसए	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
एलएसबीएस	लॉन्ग स्पैन ब्रिज
एलएसडीजीएस	सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
एलटी-एलईडीएस	दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति
एलडब्ल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
एमएंडए	विलय और अधिग्रहण
एमएएचएसआर	मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल
एमएएस	सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण
एमबीबीएस	बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी
एमसीएएस	मॉडल रियायत समझौते
एमसीएलआर	निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत
एमडीबी	बहुपक्षीय विकास बैंक
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमएफएन	मोस्ट फेवर्ड नेशन
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआई	मिशन इंद्रधनुष
एमआईसीए	क्रिप्टो संपत्ति में बाजार
एमआईसीई	बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां
एमआईडीएच	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमआईएसएस	संशोधित ब्याज अनुदान योजना
एमएम	पैसा गुणक
एमएमएफ	मानव निर्मित फाइबर
एमएमआर	मातृ मृत्यु अनुपात
एमएमटी	लाख मीट्रिक टन

एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएलई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओवीसीडीएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमपीआई	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएच	मेटी स्टार्ट-अप हब
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईडी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटी	मीट्रिक टन
एमटीओई	तेल समतुल्य मिलियन टन में
एमटीपीए	मिलियन टन प्रति वर्ष
एमयूडीआरए	सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमों के विकास और फनर्वित एजेंसी
एमवीटी	चिकित्सा मूल्य पर्यटन
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएबीएफआईडी	बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक
एनएडीसीपी	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
एनएएफसीसी	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष
एनएआईएस	सूचना सोसायटी के लिए राष्ट्रीय एजेंसी
एनएपी	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम
एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
एनएपीएस	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना
एनएएसडीएक्यू	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन
एनएएसएससीओएम	सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ
एनबीसी	शुद्ध उधारी सीमा
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीएईआर	अनुप्रयुक्त और आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद
एनसीएफ	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
एनसीजीटीसी	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी
एनसीक्यूजी	नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य
एनसीआरएफ	राष्ट्रीय ऋण ढांचा
एनसीएस	राष्ट्रीय कैरियर सेवा
एनसीएस	गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनईईपीसीओ	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एनईईआर	नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
एनई-एफएमएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष प्रबंधन प्रणाली
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति

एनईएसएल	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
एनएफएपी	राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएफएसएम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनएचईक्यूएफ	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा
एनएचएम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एनएचपी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
एनएचएस	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनआईडीएचआई	आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस
एनआईडीएचआई	नवाचारों के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल
एनआईआई	कुल ब्याज आय
एनआईएनएल	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
एनआईपी	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनएल	नई पंक्तियाँ
एनएलईएम	आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एनएलपी	राष्ट्रीय रसद नीति
एनएलपी-मेरीन	राष्ट्रीय रसद पोर्टल-समुद्री
एनएमसी	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
एनएमएमएस	राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर
एनएमपी	राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
एनएमआर	नवजात मृत्यु दर
एनएनपीए	नेट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
नॉन-एसईडी	गैर-संप्रभु बाह्य ऋण
एनपीए	गैर-निष्पादित संपत्ति
एनपीसीसी	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीसीआईएल	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इंटरनेशनल
एनपीआईएसएचएस	घरेलू और गैर-लाभकारी
एनपीपीए	राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
एनपीपीपी	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण नीति
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन योजना
एनआरसीपी	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
एनआरआई	विदेश वाले प्रवासी भारत
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनएसपी	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एनएसएस-ईयूएस	एनएसएस रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण
एनएसडब्ल्यूएस	राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली
एनटीबीएस	गैर टैरिफ बाधाएं
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनडब्ल्यूएस	राष्ट्रीय जलमार्ग
ओसीबी	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय
ओसीसी	मुद्रा नियंत्रक का कार्यालय
ओसीईएन	क्रेडिट सक्षमता नेटवर्क खोलें
ओसी-एमआईएस	ऑक्सीकेयर प्रबंधन सूचना प्रणाली
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
ओडीएल	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा
ओडीओपी	एक जिला एक उत्पाद
ओडी-ओपी	एक जिला-एक उत्पाद
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
ओएनडीसी	डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम
ओएनओआरसी	वन नेशन वन राशन कार्ड
ओओपीई	आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय
ओपीईसी	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
ओपेएक्स	परिचालन व्यय
ओएसएटी	आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट
पीए	अनंतिम वास्तविक
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि साख समितियां
पीएटी	कर के बाद लाभ
पीएटी	प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार
पीबीई	निर्यात का डाक बिल
पीसीए	शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई
पीसीआर	प्रावधान कवरेज अनुपात
पीसीएस	पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम
पीडीसीएस	परियोजना विकास प्रकोष्ठ
पीडीएमसी	लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीई	निजी इक्विटी
पीई	अनंतिम अनुमान
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
पीएफसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीएफआरडीए	पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण
पीएफआरडीए	पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण

पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीआईबी	प्रेस सूचना ब्यूरो
पीआईबीओएस	निर्माता, आयातक और ब्रांड स्वामी
पीकेवीवाई	परम्परागत कृषि विकास योजना
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएलआई	प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव
पीएलआईएसएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
पीएम केयर्स	प्रधान मंत्री की नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत
पीएम मित्र	प्रधान मंत्री मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान
पीएम श्री	राइजिंग इंडिया के लिए प्रधान मंत्री स्कूल
पीएम एसवीए निधि	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना
पीएमएवाई-जी	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
पीएमएवाई-यू	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
पीएमबीजेकेएस	प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र
पीएमबीजेपी	प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना
पीएमईएसी	प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमएफएमई	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का प्रधान मंत्री का औपचारिककरण
पीएमजी	परियोजना निगरानी समूह
पीएमजीकेएवाई	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएमजीकेवाई	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमआई	क्रय प्रबंधकों की सूची
पीएमजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीएमजेजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएम-किसान	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
पीएमकेके	प्रधानमंत्री कौशल केंद्र
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
पीएम-कुसुम	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीएमएमएसवाई	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
पीएमएमवीवाई	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
पीएमपी	चरणबद्ध विनिर्माण योजना
पीएम-सौभाग्य	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमएसएसवाई	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पीएम-एसवाईएम	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन
पीएमयूवाई	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
पीएमवीवीवाई	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
पीओएल	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक
पोषण	समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना
पीपीएसी	पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल
पीपीपी	सरकारी निजी कंपनी भागीदारी

पीपीपी	क्रय शक्ति समता
पीपीपीएसी	सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति
प्रशस्त	प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल
पीआरआईएस	पंचायती राज संस्थाएं
पीएसए	प्रेशर स्वींग एडसोरप्सन
पीएसबीएस	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
पीएसएल	प्राथमिकता क्षेत्र उधार
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवी	फोटोवोल्टिक
पीवीबीएस	निजी क्षेत्र के बैंक
पीडब्ल्यूपीएस	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर
क्यूई	क्वार्टर एंडिंग
क्यूईएस	त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण
क्यूएफएसए	कतर वित्तीय सेवा प्राधिकरण
क्यूआईपी	योग्य संस्थागत प्लेसमेंट
आरएंडडी	अनुसंधान और विकास
रफ्तार	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण
आरएएमपी योजना	एमएसएमई प्रदर्शन योजना को बढ़ाना और उसमें तेजी लाना
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीबी	अनुपालन बोझ को कम करना
आरसीईपी	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
आरसीएस	क्षेत्रीय संपर्क योजना
आरडीसी	अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ
आरई	संशोधित अनुमान
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आरईई	दुर्लभ पृथ्वी तत्व
आरईईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरईआईटी	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट
आरईआईटीएस	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट
आरईआरए	रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम
आरईआरए	रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम
आरईवीपीएआर	राजस्व प्रति उपलब्ध कमरा
आरएफआईडी	रेडियो फीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरएफक्यू	योग्यता के लिए अनुरोध
आरजीएसए	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरएचएस	दाहिने हाथ की ओर
आरआईसी	सड़क और अवसंरचना उपकर
आरकेएम	रूट किलोमीटर
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरएमएनसीएएच+एन	प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण
आरएमएस	रबी विपणन मौसम
आरएनएफसी	रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क

आरओए	संपत्ति पर वापसी
आरओडीटीईपी	निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट
आरओई	लाभांश
आरओएससीटीएल	राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट
आरओटी	फनर्वास-संचालन-स्थानांतरण
आरओडब्ल्यू	मार्ग - अधिकार
आरपीएल	पहले की सीख की मान्यता
आरपीओ	नवीकरणीय खरीद दायित्व
आरएसईटीआई	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीएएस	क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था
आरटीई	शिक्षा का अधिकार
आरटीजीएस	रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
आरडब्ल्यूएएस	जोखिमपूर्ण संपत्ति
एसएंडपी	मानक और गरीब
साथी	आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली
समर्थ	स्मार्ट एडवांस्ड मैन्यफैक्चरिंग और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब
एसएआरएफएईएसआई	वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और फनर्निर्माण और प्रतिभूतियों के हित का प्रवर्तन
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई	कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय
एसबीएम(जी)	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण
एसबीएसटीए	वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय
एससीबीएस	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीसीएल	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
एससीएस	उप केंद्र
एसडीएफ	स्थायी जमा सुविधा
एसडीजीएस	सतत विकास लक्ष्यों
एसडीएलएस	राज्य विकास ऋण
एसडीआरएस	विशेष रेखा - चित्र अधिकार
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना
एसईडी	संप्रभु बाहरी ऋण
एसजीआरबीएस	सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स
एसजीआरसी	राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति
एसजीएसटी	राज्य माल और सेवा कर
एसएचसीएस	उप स्वास्थ्य केंद्र
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचजी-बीएलपी	एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना
एसएचजीएस	स्वयं सहायता समूह
एसआईएएम	सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यफैक्चरर्स
एसआईडीएस	छोटे द्वीप विकासशील राज्य
एसआईपी-ईआईटी	ईएंडआईटी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन
एसएमएएफ	कृषि-वानिकी पर उप-मिशन
एसएमएएम	कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन
एसएमईएस	छोटे और मध्यम उद्यम

एसओपी	मानक संचालन प्रक्रियाएं
एसपीईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना
एसपीआई	फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाना
एसपीएसई	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
एसआरएफ	विशेष फनर्वित्त सुविधा
एसआरएस	नमूना पंजीकरण प्रणाली
एसएसबीएस	मानक-सेटिंग निकाय
एसएसएस	प्रतिभूति निपटान प्रणाली
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीएआरएस	राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण
एसटीटी	लघु अवधि प्रशिक्षण
स्वामित्व	ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण
एसवीईपी	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम
एसडब्ल्यूआईएफटी	व्यापार के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस
टीएटी	बदलाव का समय
टी-बिल्स	राजकोष चालान
टीडीजीवीए	टूरिज्म डायरेक्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीईडीएस	तकनीकी विशेषज्ञ संवाद
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
टीएचई	कुल स्वास्थ्य व्यय
टीआईडीई	प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास
टीकेएम	ट्रैक किलोमीटर
टीएनएलसी	टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क
टीओटी	टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर
टीआर	व्यापार भंडार
ट्राई	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
टीआरईडीएस	ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम
टीआरआईएफईडी	ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीटीएस	यात्रा और पर्यटन हितधारक
यू5एमआर	पांच से कम मृत्यु दर
यूएई	संयुक्त अरब अमीरात
उडान	उड़े देश का आम नागरिक
यूडीआईएसई	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआईपी	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम
यूके	यूनाइटेड किंगडम
उमंग	नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन
यूएनसीटीएडी	व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड
यूएनडब्ल्यूटीओ	संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन

यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूआर	बेरोजगारी दर
यूएस एफईडी	यूएस फेडरल रिजर्व
यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसओएफ	यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड
यूटीएस	संघ राज्य क्षेत्र
वीए	वर्चुअल एसेट
वीएएसपी	वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर
वीएटी	मूल्य वर्धित कर
वीसी	उद्यम पूंजी
वीडीए	वर्चुअल डिजिटल एसेट्स
वीजीएफ	वायबिलिटी गैप फंडिंग
वीआईपी	वेंटिलेटेड इम्प्रूव्ड पिट
वीआईएक्स	अस्थिरता सूचकांक
वीओएस	ग्राम संगठन
वीआरआर	परिवर्तनीय रेपो दर
डब्ल्यूएसीआर	भारित औसत कॉल दर
डब्ल्यूएडीटीडीआर	भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर
डब्ल्यूएएलआर	भारित औसत उधार दर
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक आउटलुक
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूपीआर	श्रमिक जनसंख्या अनुपात
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
वाईओवाई	वर्ष दर वर्ष
जेडबीएनएफ	शून्य बजट प्राकृतिक खेती

तालिकाओं की सूची

तालिका सं.	तालिका	पृष्ठ सं.
I.1	वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के कारण सभी देशों में विकास के पूर्वानुमान में गिरावट आई है	7
I.2	भारत को छोड़कर अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मूल ऋण 2008 की तुलना में अधिक है	8
II.1	वर्ष 2000 और 2002 के बीच भारत में सूखे की घटना, प्रभावित लोगों की संख्या और नुकसान	27
II.2	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों के डिक्रिमिनलाइजेशन (वैधीकरण) का स्नैपशॉट	32
II.3	अवधियों के बीच समानांतर 1998-2002 और 2014-2022	38
III.1	अप्रैल से नवंबर 2022 तक केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतकों का स्थिर प्रदर्शन	44
III.2	अप्रैल से नवंबर 2022 तक केंद्र सरकार के कर में वृद्धि	45
III.3	केन्द्र सरकार के गैर-कर राजस्व की प्रवृति	49
III.4	केंद्र का अवसंरचना से जुड़े क्षेत्रों पर आधारित पूंजीगत व्यय	51
III.5	केंद्र सरकार द्वारा किए गए राजस्व व्यय की प्रमुख मदें	52
III.6	केंद्र से राज्यों को किए गए हस्तांतरण का विवरण (राज्यों के लिए अंतरण के अलावा)	56
III.7	15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों को अनुदान का आवंटन	56
III.8	वित्तीय वर्ष 2023 में पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना का ब्यौरा	60
III.9	केंद्र सरकार की ऋण स्थिति (लाख करोड़ रु. में)	62
IV.1	मौद्रिक योग में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	81
IV.2	सभी बैंक समूहों में ऋण और जमा दरों में अंतरण	84
IV.3	जी-सेक में कुल एकमुश्त व्यापार गतिविधि का श्रेणी-वार हिस्सा (प्रतिशत)*	85
IV.4	30 सितंबर के अनुसार संकटग्रस्त आस्तियों का बचाव (राशि करोड़ रुपये में)	93
IV.5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से वसूल की गई राशि (राशि करोड़ में)	94
IV.6	प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाना	95
IV.7	वित्त वर्ष 2023 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भारत ने अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया	96
IV.8	इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी में गिरावट आई	99
IV.9	वित्त वर्ष 2022 में डीमैट खातों में तेज वृद्धि देखी गई	99
IV.10	इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी डेरिवेटिव्स में टर्नओवर सांख्यिकी में वृद्धि हुई	99
IV.11	म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम में वृद्धि	100
IV.12	इक्विटी-उन्मुख योजनाओं में शुद्ध प्रवाह देखा गया	100
IV.13	एफपीआई के तहत संरक्षित संपत्तियां में वद्धि	101
IV.14	एफपीआई में दर्ज बहिर्वाह के अनुसार शुद्ध निवेश	101
IV.15	चयनित बाजारों में कुल पोर्टफोलियो प्रवाह का रुझान (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	102
IV.16	सरकारी बीमा योजनाएं और प्रगति	112
IV.17	भारत के पेंशन क्षेत्र का प्रदर्शन	115
V.1	सीपीआई-सी के आधार पर औसतन वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति (प्रतिशत) (आधार 2012=100)	120
V.2	डब्ल्यूपीआई (प्रतिशत) के आधार पर औसतन वार्षिक थोक मुद्रास्फीति (आधार 2011-12=100)	130
V.3	मौद्रिक नीति संबंधी विवरण- सख्त मौद्रिक नीति	138
VI.1	सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के व्यय में रुझान (संयुक्त केंद्र और राज्य)	148
VI.2	वैश्विक एचडीआई 2021 में भारत की स्थिति एवं रुझान	149
VI.3	चार श्रम संहिताओं के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा नियमों की स्थिति	154
VI.4	सामान्य स्थिति में रोजगार के रुझान	158

VI.5	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में रोजगार के रुझान	159
VI.6	क्यूईएस के अनुसार क्षेत्रवार श्रमिकों की अनुमानित संख्या	166
VI.7	रोजगार की शर्तों के अनुसार श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण (त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार)।	167
VI.8	सभी आयु समूहों में मुख्य उद्योगों के लिए ईपीएफओ पेरोल डेटा	170
VI.9	स्कूल सकल नामांकन अनुपात	175
VI.10	स्कूल ड्रापआउट रेट	176
VI.11	मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या में रुझान	176
VI.12	स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार	177
VI.13	उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन	180
VI.14	उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की संख्या	181
VI.15	औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का वितरण	182
VI.16	औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण और ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का क्षेत्रवार प्रतिशत	183
VI.17	स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में सुधार	186
VI.18	मृत्यु दर संकेतकों में रुझान	187
VI.19	स्वास्थ्य ढांचे में प्रगति	191
VI.20	ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष	202
VI.21	डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगति	204
VI.22	मनरेगा के तहत प्रगति	205
IX.1	औद्योगिक घटकों का विकास एंव भागीदारी (प्रतिशत में)	261
IX.2	विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)	268
IX.3	उद्योग उपखंडों में नियोजित ऋण में वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)	270
XI.1	भारत के व्यापार के प्रमुख पहलू (कैलेंडर वर्षवार)	315
XI.2	सेवा व्यापार का लचीला प्रदर्शन	319
XI.3	विदेशी ऋण बकाया	337
XI.4	भारत के प्रमुख विदेशी ऋण संकेतक स्थिरता का चित्र	338
XII.1	रेलवे पर अवसंरचना पूंजीगत व्यय में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है	354
XII.3	अखिल भारतीय स्थापित क्षमता मोड-वार (जीडब्ल्यू)	359
XII.4	अखिल भारतीय सकल विद्युत उत्पादन मोड-वार	359

चित्रों की सूची

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
I.1	रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण जिंसों की कीमतों में तीव्र वृद्धि; कीमतें अभी भी संघर्ष - पूर्व स्तर तक नहीं पहुंची हैं	4
I.2क	विकसित अर्थव्यवस्थायें	4
I.2ख	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं	4
I.3क	विकसित अर्थव्यवस्थायें	5
I.3ख	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं	5
I.4क	एई में 10 वर्षीय बॉन्ड	6
I.4ख	ईएमई में 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड	6
I.5	फेडरल फंड्स रेट जनवरी 2022 से संचयी 425 आधार अंकों से बढ़ाया गया है, जिससे ईएमई और एई से पूंजी निकल गयी है।	6
I.6	अगस्त 2022 से वैश्विक समग्र पीएमआई संकुचन क्षेत्र में	7
I.7	खुदरा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि गिर रही है	7
I.8क	चीन के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) घट रही है	8
I.8ख	चीन की खुदरा बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) कम हो रही है	8
I.9	आर्थिक विकास लचीला बना हुआ है	9
I.10क	वास्तविक जीवीए में वर्ष दर वर्ष संवृद्धि	10
I.10ख	वास्तविक जीडीपी घटकों के हिस्से	10
I.11	सीपीआई मुद्रास्फीति आरबीआई की लक्ष्य सीमा में वापस आ गई	10
I.12	भारतीय रुपये ने अन्य ईएमई की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया	10
I.13	बढ़ा हुआ चालू लेख घाटा	11
I.14	सीएडी के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार	11
I.15	व्यापार धीमा होने के कारण शिपिंग माल ढुलाई लागत में कमी	12
I.16	वैश्विक मंदी के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात का हिस्सा बढ़ता है	12
I.17	वित्त वर्ष 23 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत के विकास अनुमान	12
I.18	बढ़ी हुई क्षमता उपयोग और व्यावसायिक भाव	13
I.19क	वित्त वर्ष 15 के बाद वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में निजी खपत सबसे अधिक पर	14
I.19ख	उपभोक्ता विश्वास में सुधार	14
I.20	आवास के लिए बैंक ऋण में वृद्धि गिरते हाउसहोल्ड्स को संपुरित कर रहा है	14
I.21	वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 23 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय औसतन 13 की दर से बढ़ा	15
I.22	कैपेक्स पिछले पांच वर्षों में दोगुना हो गया	16
I.23	निजी निवेश आशा के अनुरूप बना हुआ है	16
I.24	कर संग्रह में उछाल (अप्रैल-नवंबर)	16
I.25	राजस्व व्यय में सीमित वृद्धि	16
I.26	एमएसएमई के बैंक ऋण में दोहरे अंकों में वृद्धि	17
I.27	एससीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट	18
I.28	प्रावधान (प्रोविजनिंग) कवरेज अनुपात	18
I.29	बढ़ता कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल	18
I.30	कॉरपोरेट बॉन्ड के निजी नियोजन में कमी	18
I.31	उच्च ब्याज/हेजिंग लागत में ईसीबी और एफसीसीबी को निधियों का कम आकर्षक स्रोत बना दिया	18
I.32	मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं की स्थिरता	19
I.33	शहरी बेरोजगारी पांच वर्षों के निम्नतम स्तर पर	20

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
I.34	वित्त वर्ष 2022 में एमएसएमपी द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी में महामारी- पूर्व के स्तर को पार किया	20
I.35	ईसीएलजीएस में एमएसएमई को अपनी सम्पत्ति की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता की	20
I.36	ग्रामीण कल्याण सूचकांको में सुधार	21
I.37	वैश्विक आर्थिक वृद्धि और व्यापार में मंदी	22
II.1	वर्ष 2000-2003 में निवेश के उदारीकरण को बढ़ावा देने के बाद भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि	26
II.2	सकल राजकोषीय घाटा (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) (जीडीपी का)	26
II.3	कुल संपत्ति के के रूप में एससीबी का सकल एनपीए	26
II.4	एससीबी द्वारा गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि	27
II.5	अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई (1998)	27
II.6	डॉट-कॉम बबल संकट के कारण कई देशों में मंदी आई, जिससे वैश्विक अनिश्चितता बढ़ गई	28
II.7	केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ रहा है	29
II.8	महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षमता में विकास (पहले उपलब्ध	30
II.9	औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि	33
II.10	2014-15 के दौरान सकल एफडीआई/जीडीपी में संरचनात्मक बदलाव	35
II.11	अधिकांश 2010 के लिए जीडीपी गैप के लिए त्रैमासिक क्रेडिट नकारात्मक रहा	37
III.1	पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के घाटे की प्रवृति- राजकोषीय समेकन के मार्ग पर	43
III.2	सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में लक्षित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के ट्रैक पर	43
III.3	केंद्र सरकार के टैक्स प्रोफाइल की संरचना (वित्तीय वर्ष 2023 ब.अ.)	46
III.4	अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान केंद्र के प्रत्यक्ष करों में वृद्धि उनके दीर्घावधि औसत से अधिक है	46
III.5	अप्रैल से दिसंबर तक संचयी सकल जीएसटी संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष उच्च वृद्धि	47
III.6	पिछले कई वर्षों से मासिक सकल जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि	47
III.7	केंद्र सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का बढ़ता हुआ अंश	50
III.8	केंद्र सरकार का जीडीपी अनुपात में कैपेक्स पूर्व के दीर्घावधि औसत से अधिक है	50
III.9	अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में उच्च वृद्धि	50
III.10	संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उच्च-ब्याज भुगतान को कम करने	53
III.11	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के घाटे का समेकन	55
III.12	अप्रैल-नवंबर के दौरान राज्यों का कम राजकोषीय घाटा	55
III.13	कुछ देशों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक शेष राशि में वृद्धि	61
III.14	वैश्विक महामारी के कारण आई तेजी के बाद केंद्र सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात में सुधार	62
III.15	सार्वजनिक ऋण में बाह्य देयता का अनुपात	63
III.16	जीडीपी के अनुपात में सामान्य सरकार की देनदारियां वित्त वर्ष 21 में प्राप्त अपने चरम बिन्दु से नीचे आ गई हैं	63
III.17	जीडीपी के अनुपात में सामान्य सरकार की देनदारियां वित्त वर्ष 21 में प्राप्त अपने चरम बिन्दु से नीचे आ गई हैं	64
III.18	भारत के लिए विकास-ब्याज दर का अंतर	65
III.19	कई देशों में वर्ष 2005 और वर्ष 2021 के जीडीपी अनुपात की सामान्य सरकारी ऋण के साथ तुलना	65
IV.1	पॉलिसी दरें	80
IV.2क	व्यापक मुद्रा की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में गिरावट	81
IV.2ख	अभिसरण मुद्रा गुणक (एमएम) उपाय	81
IV.3क	व्यापक धन की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में गिरावट	82
IV.3ख	ओवरनाइट कॉल मनी दरें अब एलएएफ कॉरिडोर के भीतर सुव्यवस्थित चलन में हैं	82
IV.4	घरेलू ऋण देने और जमा दरों में वृद्धि	83
IV.5	जुलाई से जी-सेक प्रतिफल में कमी आ रही है, तेल की कीमतों में गिरावट और वैधिक बांड प्रतिफल द्वारा समर्थित	84
IV.6क	एससीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट	86

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
IV.6ख	प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात	86
IV.7	जीएनपीए अनुपात में व्यापक आधार पर सुधार	86
IV.8	पूंजी पर्याप्तता अनुपात आवश्यकता मानदंडों से काफी ऊपर है	87
IV.9क	आरओई- वार्षिक	87
IV.9ख	आरओए- वार्षिक	87
IV.10	अप्रैल 2022 से गैर-खाद्य बैंक ऋण उच्चतम वृद्धि	88
IV.11	क्षेत्रीय गैर-खाद्य बैंक ऋण में व्यापक आधारित वृद्धि	88
IV.12	एनबीएफसी को और उनके द्वारा संवितरित ऋण में वृद्धि	89
IV.13	जीएनपीए अनुपात में गिरावट सभी क्षेत्रों में एनबीएफसी की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार	90
IV.14	एनबीएफसी का प्रदर्शन मजबूत पूंजी स्थिति के साथ आरओए की भरपाई करना	90
IV.15	उद्योग में मामूली सुधार के साथ सभी क्षेत्रों में एनबीएफसी द्वारा ऋण संवितरण में मजबूत वृद्धि	91
IV.16	स्थापना से सीआईआरपी की स्थिति (सितंबर 2022 तक)	91
IV.17	क्षेत्रवार सीआईआरपी की स्थिति (सितंबर 2022 तक)	92
IV.18	विनिर्माण क्षेत्र में चल रहे सीआईआरपी का क्षेत्रीय विभाजन	92
IV.19	सेवा क्षेत्र में चल रहे सीआईआरपी का क्षेत्रीय विभाजन	92
IV.20	भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी से सुधार देखा गया	97
IV.21	इंडिया वीआईएक्स में गिरावट का रुख देखा गया	97
IV.22	वित्तीय वर्ष 23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान भारतीय सूचकांकों में वार्षिक अस्थिरता अपेक्षाकृत कम रही	98
IV.23	निफ्टी 50 वैश्विक बाजारों की तुलना में महंगा है, हालांकि अपने 5 साल (2017-2021) के औसत की तुलना में अभी भी कम है	98
IV.24	हाल के वर्षों के दौरान एफपीआई बहिर्गमन के लिए डीआईआई निवेश ने बराबर करने वाले बल के रूप में कार्य किया	102
IV.25क	2021 में जीवन-बीमा प्रीमियम की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन	110
IV.25ख	2021 में गैर-जीवन बीमा प्रीमियम की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन	110
IV.26क	बीमा प्रवेश में लगातार वृद्धि	111
IV.26ख	बीमा घनत्व में दो अंकों की वृद्धि	111
V.1	कैलेंडर वर्ष 2022 में रिकॉर्ड उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति	119
V.2	विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति	119
V.3	खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट	121
V.4	'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह द्वारा प्रेरित खुदरा मुद्रास्फीति	122
V.5	प्रमुख समूहों/उप-समूहों में खुदरा मुद्रास्फीति	123
V.6	वित्त वर्ष 23 में खाद्य मुद्रास्फीति के प्रेरक - सब्जियां, अनाज, दूध और मसालें	124
V.7	वित्त वर्ष 23 में टमाटर की कीमत और 'सब्जियों' की मुद्रास्फीति में उछाल	124
V.8	खाद्य तेलों में आयातित मुद्रास्फीति	125
V.9	खाद्य तेलों का आयात	125
V.10	खाद्य तेलों की संयत खुदरा कीमत	126
V.11	शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति	128
V.12	वित्त वर्ष 23* में अधिकांश राज्यों में उच्च खुदरा मुद्रास्फीति	128
V.13	वित्त वर्ष 23* में अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतर ग्रामीण मुद्रास्फीति	129
V.14	मूल और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट	131
V.15	वित्त वर्ष 23* में थोक मुद्रास्फीति के प्रेरक - ''प्राथमिक सामग्री'' और ''ईंधन और विद्युत''	131
V.16	वैश्विक वस्तु कीमतों में कमी	132
V.17	कच्चे तेल की कीमतों में कमी	134

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
V.18	प्रमुख डबल्यूपीआई की मुद्रास्फीति सहित मुख्य सीपीआई- मुद्रास्फीति अभिसरण	135
V.19	मूल मुद्रास्फीति में अभिसरण सीपीआई-सी बनाम डब्ल्यूपीआई	135
V.20	खाद्य मुद्रास्फीति में अभिसरण सीपीआई-सी बनाम डब्ल्यूपीआइ	136
V.21	सीपीआई (ईंधन और विद्युत) और डब्ल्यूपीआई (ईंधन और बिजली) के बीच मुद्रास्फीति दरों का अभिसरण	136
V.22	खुदरा और थोक ऊर्जा मुद्रास्फीति दरों में अभिसरण	137
V.23	व्यापार और घरेलू मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं कम हो रही हैं	137
V.24	मेट्रो शहरों के लिए एचपीआई - 'अहमदाबाद' और 'हैदराबाद' में उछाल	140
V.25	अखिल भारतीय समग्र एचपीआई - आवास बाजार में सुधार	141
VI.1	सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के व्यय में रुझान	147
VI.2	ई-श्रम पोर्टल के तहत संचयी पंजीकरण	159
VI.4	महिला श्रम बल भागीदारी दर में बदलाव	160
VI.5	त्रैमासिक शहरी रोजगार संकेतक	165
VI.6	तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार श्रमिकों की अनुमानित संख्या	166
VI.7	तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार कुल रोजगार का क्षेत्रवार हिस्सा	166
VI.8	एएसआई के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कारखानों में लगे कुल व्यक्ति	168
VI.9	एएसआई के अनुसार कारखानों में रोजगार के रुझान	168
VI.10	ईपीएफओ में ग्राहकों की शुद्ध वृद्धि	170
VI.11	मनरेगा के तहत काम मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या	171
VI.12	मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या	172
VI.13	मनरेगा के तहत पूर्ण कार्यों का हिस्सा (गणना के अनुसार)	172
VI.14	ग्रामीण मजदूरी में रुझान	174
VI.15	उच्च शिक्षा में छात्रों का कुल नामांकन	180
VI.16	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय और जेब से व्यय	188
VI.17	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय और निजी स्वास्थ्य व्यय	189
VI.18	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में जेब से व्यय - 2018-19 के लिए राज्य-वार	189
VI.19	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय - 2018-19 के लिए राज्यवार	189
VI.20	कोविड-19 वैक्सीन के साथ वयस्क आबादी का संचयी प्रतिशत	195
VII.1	विभिन्न देशों (प्रतिज्ञा वर्ष दंडा रेख के ऊपर है) की निवल शून्य प्रतिज्ञा	217
VII.2	एनएपीसीसी के आठ राष्ट्रीय मिशनों की प्रगति	221
VII.3	आईएसएफआर 2013 से आईएसएफआर 2021 तक कार्बन स्टॉक	224
VII.4	भारत में मैंग्रोव आवरण (वर्ग किमी)	225
VII.5	दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता (मीगावाट)	226
VII.6	भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	226
VII.7	वर्ष 2029-30 के लिए संस्थापित क्षमता का इष्टतम मिश्रण	227
VII.8	बिजली की प्रति किलोवाट औसत कार्बन डाइऑक्साइड (ब्व्2) उत्सर्जन का दर	227
VII.9	राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मुख्य विशेषताएं।	228
VII.10	हरे और भूरे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की स्तरीकृत लागत (एलसीओएच)।	229
VII.11	चयनित खनिजों के प्रमुख उत्पादक देश, वर्ष 2019 और 2025	230
VII.12	वर्ष 2021 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना (अमेरिकी बिलियन डॉलर)	232
VII.13	बाघों की संख्या	239
VII.14	शेरों की संख्या	239
VIII.1	कोविड-19 महामारी के कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने लोचदार वृद्धि	244

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
VIII.2	कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा देना	244
VIII.3	कृषि के लिए भारत की बिजली खपत (वार्षिक)	245
VIII.4	भारत के खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि (मिलियन टन)	245
VIII.5	चयनित खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹/क्विंटल)	246
VIII.6	कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि (₹ लाख करोड़)	247
VIII.7	यद्यपि कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में अभी भी फसल क्षेत्र का प्रमुख योगदान है, पशुधन क्षेत्र (प्रतिशत में) की ओर बढ़ रहा है	252
VIII.8	20 अक्टूबर 2022 तक बहु-राज्य सहकारी समितियों वाले शीर्ष दस राज्य	254
VIII.9	2022-23 और 1 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिमियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न का आवंटन (लाख टन)	257
VIII.10	2014-15 से भारत सरकार द्वारा जारी कुल खाद्य सब्सिडी (हजार करोड़)	258
IX.1	निजी क्षेत्र में निवेश से गति प्राप्त करना	263
IX.2	पीएमआई उत्पादन विस्तारक क्षेत्र में बना हुआ है	266
IX.3	आईआईपी के उप-सूचकांक मजबूत गति से बढ़ रहे हैं (अप्रैल-अक्टूबर)	266
IX.4	प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के घटकों में स्थिर वृद्धि	266
IX.5	उच्च वर्षा द्वारा सीमित जीवीए निर्माण (विनिर्माण उत्पादन के लिए एक प्रॉक्सी)	267
IX.6	भंडार में बिल्ड-अप और बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता के साथ जीवीए विनिर्माण धीमा है	267
IX.7	एमएसएमई द्वारा संचालित उद्योग में दो अंकों की ऋण वृद्धि	269
IX.8	अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान 2022-23 में क्षेत्र-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह	271
IX.9क	निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी	272
IX.9ख	समग्र जीवीए और निर्माणकारी जीवीए में एमएसएमई की हिस्सेदारी	272
IX.10	वित्त वर्ष 22 में एमएसएमई द्वारा जीएसटी भुगतान, महामारी-पूर्व स्तर को पार कर गया है।	274
IX.11	ईसीएलजीएस सहायता प्राप्त एमएसएमई, उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार	274
IX.12	इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मजबूत वृद्धि (अप्रैल-अक्टूबर)	275
IX.13	पर्याप्त कोयला उत्पादन	278
IX.14	कोयला भंडार में वृद्धि	278
IX.15	रूइस्पात उत्पादन और खपत में वृद्धि	279
IX.16	वित्त वर्ष 23 के दौरान लौह और इस्पात निर्यात में मामूली सुधार	279
IX.17	कपड़ा निर्यात में कमी आई, जबकि रेडीमेड गारमेंट निर्यात में तेजी आई है।	280
IX.18	कपड़ा उद्योग में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह अभी तक बहाल नहीं हुआ है	280
IX.19	फार्मास्युटिकल निर्यात में अत्यधिक वृद्धि	281
IX.20	फार्मा क्षेत्र में एफडीआई का अधिक अंतर्वाह	281
IX.21	औषधि क्षेत्र में विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए तीन पीएलआई योजनाएं	281
IX.22	ऑटोमोबाइल की वृद्धिशील बिक्री	282
IX.23	कमजोर वैश्विक मांग के बीच ऑटोमोबाइल निर्यात में मंदी	282
IX.24	ऑटोमोबाइल की वृद्धिशील बिक्री	283
IX.25	खपत बढ़ाने वाली प्रोत्साहन योजनाएं	283
IX.26	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं	284
IX.27	मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 24 उप-क्षेत्र	285
X.1	सेवा क्षेत्र में व्यापक आधार वाली वृद्धि	293
X.2	वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई।	294
X.3	पीएमआई सेवाएं भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद विस्तार क्षेत्र में बनी रहीं	294

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
X.4	अप्रैल 2022 से सेवा क्षेत्र द्वारा ऋण लेने में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई	295
X.5	भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सेवा निर्यात लचीला बना रहा।	296
X.6	पूर्व-महामारी स्तर के पास होटल अधिभोग दर	299
X.7	औसत दैनिक दर (एडीआर) और राजस्व प्रति उपलब्ध कक्ष (रेवपीएआर) में सुधार	299
X.8	अभी भी भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) महामारी पूर्व स्तर से नीचे है	299
X.9	हाउसिंग सेल्स और लॉन्च में निरंतर वृद्धि, पूर्व-महामारी के स्तर को पार करनाचित्र	302
X.10	इन्वेंटरी ओवरहैंग में गिरावट	302
X.11	2020 और 2022 के बीच वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में शीर्ष पारदर्शिता सुधारक	303
X.12	IT-BPM निर्यात का भौगोलिक वितरण (हार्डवेयर को छोड़कर)	304
X.13	FY22 में राजस्व का खंड-वार ब्रेक-अप	304
X.14	2027 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर का करने के लिए फैशन, किराना और सामान्य व्यापार	306
XI.1	वैश्विक पण्य व्यापार में वृद्धि वास्तविक और पूर्वानुमान	314
XI.2	भारतीय व्यापार से वैश्विक व्यापार से स्तरों के साथ गति आ रही है	315
XI.3	भारत का पण्य निर्यात	316
XI.4	भारत का पण्य आयात	317
XI.5	पण्य का आयात, निर्यात और व्यापार संतुलन की प्रवृत्ति	318
XI.6	सेवा व्यापार में तेजी का रुझान	319
XI.7	चालू खाता शेष (बठ) परिमाण और संरचना	326
XI.8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष भारत बनाम चुनिंदा देश	327
XI.9	व्यापार की निवल अदृश्य मदों की संरचना मजबूत सेवाएं और बड़ा धन-प्रेषण	327
XI.10	2022 के दौरान विश्व के शीर्ष धन-प्रेषण प्राप्तकर्ता (अनुमानित)	328
XI.11	पूंजीगत खाता शेष परिमाण और संरचना	328
XI.12	निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	329
XI.13	निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश	329
XI.14	समग्र भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भंडार	330
XI.15	भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता (वार्षिक आयात के प्रतिशत के रूप में) एक क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य	330
XI.16	प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर	334
XI.17	6-मुद्रा और 40-मुद्रा नोमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (एनईईआर) और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (आरईईआर) (ट्रेड -वेटेड) के सूचकांक में उतार-चढ़ाव (आधार वर्ष 2015-16 = 100)	334
XI.18	सितंबर 2022 के अंत में शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश में भारत की स्थिति	335
XI.19	ऋण अनुपात 2021 के लिए क्रॉस-कंट्री तुलना	338
XII.1	अवसंरचना की मात्रा और गुणवत्ता और देशों में आर्थिक विकास का स्तर दृढ़ता से सहसंबद्ध है	343
XII.2	केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में लगातार पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है'	345
XII.3	एनआईपी के तहत परियोजनाओं की स्थिति	348

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
XII.4	एनआईपी में परिवहन क्षेत्र का दबदबा है	348
XII.5	2015-16 से राष्ट्रीय राजमार्ग/सड़क निर्माण में वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है	353
XII.6	सड़क क्षेत्र में निवेश के लिए कुल बजटीय सहायता में भारी वृद्धि	353
XII.7	कोविड -19 की अवधि के बाद रेलवे यात्री और माल यातायात में मजबूत वृद्धि देखी गई है	354
XII.8	भारतीय विमानन क्षेत्र का प्रदर्शन	356
XII.9	विभिन्न राज्यों में जलमार्गों की नौगम्य लंबाई	357
XII.10	लाइसेंस सेवा क्षेत्र-वार समग्र टेली घनत्व स्रोत दूरसंचार विभाग	361
XII.11	डलैबीमउम पोर्टल तीन आसान चरणों में योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है	367

बाक्स की सूची

बाक्स सं.	बाक्स	पृष्ठ सं.
III.1	अप्रत्यक्ष कर संग्रह की परिपक्व प्रणाली	47
III.2	पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख सुधार	53
III.3	जीएसटी और राज्यों को संसाधन प्रदान करना	56
III.4	राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में सुधार के लिए की गई पहले।	60
III.5	राजकोषीय समेकन के मार्ग के रूप में सतत विकास का मार्ग	66
IV.1	क्रॉस कंट्री विश्लेषण क्रिप्टोकरंसी का विनियमन	103
IV.2	जीआईएफटी आईएफएससी-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में उभर रहा है	106
V.1	आवश्यक खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय	126
V.2	निविष्टि मूल्यों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय	133
V.3	वर्तमान मुद्रास्फीति 1970 के दशक से कैसे भिन्न है?	138
V.4	आवासन वित्त क्षेत्र (एचएफसी) को एनएचबी समर्थन	141
VI.1	यूएनडीपी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022	150
VI.2	महिला श्रम बल भागीदारी दर में माप के मुद्दे	160
VI.3	महिला सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका	162
VI.4	नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस) परियोजना	173
VI.5	अखिल भारतीय शिक्षा समागम	182
VI.6	स्किल इंडिया मिशन की प्रगति	184
VI.7	आयुष्मान भारत के अधीन प्रगति	192
VI.8	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करना	193
VI.9	स्वास्थ्य- समर्पित कोविड अवसंरचना पर एक वर्णनात्मक व्याख्या	195
VI.10	को-विन बताने के लिए टीकाकरण की एक सफल डिजिटल कहानी	198
VI.11	मनरेगा के तहत उपलब्धियां	205
VI.12	जन स्वास्थ्य के साधन के रूप में जल जीवन मिशन	208
VI.13	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में प्रगति	213
VII.1	भारत का राष्ट्रीय स्तिर पर निर्धारित अद्यतन योगदान (एनडीसी)	222
VII.2	महत्वपूर्ण खनिज-हरित परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक	229
VII.3	प्रोजेक्ट चीता	238
VIII.1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	249
VIII.2	मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हमारा पारंपरिक स्टेपल और एक स्वस्थ विकल्प	251
VIII.3	नई राष्ट्रीय सहयोग नीति	254
IX.1	निजी पूंजी निवेश चक्र का विकास	263
IX.2	निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में सुधार	271
IX.3	अमेरिका और भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन	275
IX.4	'फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग स्टार्ट-अप्स में हालिया घटनाक्रम	286
IX.5	'फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग स्टार्ट-अप्स में हाल का घटनाक्रम'	287
X.1	वितीय वर्ष 2023 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्त्क्ाए) द्वारा बीमा क्षेत्र में पहल1	297
X.2	भारत को आकर्षक पर्यटन स्थल बनाना	300
X.3	आवासीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय	301
X.4	आईटी-बीपीएम उद्योग में प्रमुख विकास वाहक	304
X.5	अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क: भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव	308

बाक्स सं.	बाक्स	पृष्ठ सं.
X.6	दस्तावेजों का डीमैटीरियलाइजेशन: डिजिटलीकरण की अगली लहर	309
XI.1	मुक्त व्यापार समझौते	324
XI.2	विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता	331
XII.1	विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता	350
XII.2	भारतीय रेलवे की प्रमुख पहलें	355
XII.3	अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021	358
XII.4	ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को कम करना	361
XII.5	रेडियो - जुड़ी हुई तरंगें..!!	365
XII.6	एकीकृत भुगतान इंटरफेस - रीयल-टाइम भुगतान में बड़ा परिवर्तक !	369